SHRI ASHOK MITRA: Madam, we launched our freedom movement in order o negate the evil consequences of the East India Company. Is this the way a Minister should speak? I would appeal to the Prime Minister. There is still time before we go completely down under. Please do something about it

DR BIPLAB DASGUPTA Chidam bram

RE. DONATIONS TO POLITICAL PARTIES IN VIOLATION OF FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती जिस वर्ष हम मना रहे हैं उस वर्ष कुछ ऐसी जानकारियां समाचार-पत्रों के माध्यम से आई है जिससे यह पता चलता है कि हमारे लोकतंत्र को कहां खतरा पैदा हो गया। ...(**व्यवधान**)...

प्रो.विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): क्या प्रधान मंत्री साहब इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, वह जो सुपर 301 का मामला था? ...(**व्यवधान**)...

I am addressing the Prime Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You will get a reply from the Minister.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOT-RA: That is true.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not think ...*(Interruptions)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः नहीं, दैट इज टू, मिनिस्टर आज दिल्ली में नहीं दैट इज टू बट प्राइम मिनिस्टर है। यह स्पेशल 301 का मामला इतना इंपोर्टेंट है। I He can, at least, ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't think it is proper.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः नहीं, वह इतना तो हमें बता सकते हैं कि वह किसी प्रैशर में नहीं झुकेंगे। आज मिनिस्टर न होने के बाद भी After all, somebody must react.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Actually, this matter was to be raised in the form of a Calling-Attention Motion, but because the Minister had to go, it was decided that it would be raised in the House as a Zero Hour submission and that he would give clarifications to you—and, perhaps, to the House also, for sure—in writing. I do not think we should take the Prime Minister by surprise. It is a serious matter. Let him consult his Commerce Minister. When the Commerce Minister replies, I am sure the Prime Minister's inputs would be there. I must tell our Members one thing. It is very kind of them to have volunteered to speak offhand.

But it is not a common practice in our House that on a Zero Hour Mention we give a direction to a Minister to reply, not at least on such serious issues.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): ठीक है।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): उपसभापति महोदया, एक सबमीशन करना चाहूंगा। आज दिन तक हम ने जो जीरो अवर मेंशन किए या स्पेशल मेंशन किए हैं, किसी का भी जवाब नहीं आता है। हम यहां महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। इसलिए मैं आप से यह निवेदन कर रहा हूं कि जहां यहां मिनिस्टर साहब मौजूद हैं तो कुछ-न-कुछ क्लैरीफिकेशन दें अन्यथा किसी का जवाब नहीं आता है।

उपसभापतिः दवे जी, मुझे आप के साथ हमदर्दी है, सहानूभति है कि जवाब आना चाहिए क्योंकि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में कोई बात उठाते हैं तो वह बात महज उठाने के लिए होती है जवाब के लिए होती है। इस बारे में कई बार डायरेक्शन गया है। मगर यह बात "जीरो अवर" के लिए नहीं रहती। अगर स्पेशल मेंशन है तो चूंकि स्पेशल एक रूल के तहत होते हैं और उस रूल के तहत यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह टाइ फ्रेम में जवाब दे, लेकिन आप जीरो अवर में अक्सर बहुत सी बातें उठाते हैं जिन का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिए मैं मेंबर्स से उम्मीद करूंगी कि जो इस तरह के मामले हों जिन पर आप को जवाब चाहिए तो आप उन को स्पेशल मेंशन के तहत उठाइए ताकि हम जवाब दिलवाने की कोशिश करें। ...(**व्यवधान**)... अब इस पर चर्चा नहीं होगी। नरेन्दर मोहन जी, आप बोलिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): महोदया आप ने टाइ फ्रेम की बात कही है, लेकिन 6-6 महीने तक जवाब मिल पाता है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापतिः देखिए, यही खराबी है ...(**व्यवधान**)...I am sorry. One second. Please sit down. That is another derailment which takes place in the House. When a Member is rising on an issue, let us not take his time and your own time—your own name also might be somewhere. If you have any problem, please come to my chamber or the hon. Chairman's chamber: we will try to find a solution. But let us not take the time of the House which is your own. time, not mine.

श्री नरेन्दर मोहनः उपसभापति जी, आप का धन्यवाद। महोदया, मैं समझता हूं कि जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं, आदरणीय प्रधान मंत्री जी भी यहां हैं, वह मुद्दा यह है कि विदेशों से किस तरह से धन राजनीतिक दलों के लिए आ रहा है और किस प्रकार से उस धन के कारण भारत लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है। ...(**व्यवधान**)... यह बड़ी अजीब बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ...(**व्यवधान**)... उपसभापति जी, मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं अपनी बात कह सकूं और बाद में टोका-टाकी हो तो मुझे आपत्ति नहीं होगी, मगर अभी जो स्थिति है, वह गंभीर स्थिति है कि पिछले वर्षों में किस प्रकार से विदेशों से धन आया है और उस का प्रयोग राजनीतिक दलों ने अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए किया है और एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को खतरे में डाला है। महोदया, पहले यह चिंता व्यक्त की जा रही थी कि यह धन कहां से आता है, पता नहीं चलता। लोगों को उस के सोर्सेस पता नहीं चलते थे, लेकिन अब तो बहुत साफ-साफ गृह मंत्रालय ने सूचना दे दी है और डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट को भी जानकारी हो गयी है कि धन कहां से आया है, किस दल के पास आया है, किस तारीख को या है, कितना आया है और किस किस बैंक के खाते से आया है? उस सब के बावजूद भी भारत सरकार इस मामले में लगभग मौन बैठी है और किसी प्रकार दिखावे की कार्यवाही कर रही है।

महोदया, इस प्रकार का एक समाचार इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में 5 मई को प्रकाशित हुआ था। उसी के साथ मुझे पता चला कि 1993-94 में 3 ड्राफ्ट सिंगापुर से एक करोड़ के आए थे और वह प्रेसीडेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नाम आए थे। इन को कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट ने बैंक में जमा करा दिया। महोदया, यह ड्राफ्ट सिंगापुर से इंडियन बैंक के माध्यम से आए थे। इसी प्रकार वर्ष 94-95 में लगभग पौने 3 करोड़ रुपया फिर बार्कले बैंक, लंदन से आया। उस पर भी प्रेसीडेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लिखा हुआ था। इस प्रकार का जो धन आया है इस के लिए गृह मंत्रालय से धन लेने की कोई अनुमति नहीं ली गयी और न गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी, लेकिन रिजर्व बैंक जब बैंको के कातों की नॉर्मल जांच कर रहा था तब यह बात प्रकाश में आई और उस के बाद रिजर्व बैंक ने क्लासीफाइड रिपोर्ट में कहा, यह जो पहला मामला है जिस में कि इंडियन बैंक के थ्रू पैसा आया है, वह बहुत गंभीर है और पता लगाया जाना चाहिए कि यह धन कहां से आया और क्यों आया?

मैडम, फोरेन कांट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इस बात के लिए प्रतिबंध लगता है, जो इस तरह से किसी प्रकार का पैसा किसी भी राजनैतिक दल के पास आए। यह एक गंभीर अपराध है और वह इतना गंभीर अपराध है कि उसमें पांच साल की सख्त कैद और जुर्माना होता है। साधारण इंसान करे तो उसे जुमनि होते हैं तो राजनैतिक दलों पर तो बड़े जुमनि होने चाहिएं। आज इस बात को हुए कई वर्ष हो गए हैं, न जुर्माना हुआ है और न ही इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है बल्कि मुझे यह लगता है कि सांगठन करके ऐसा किया जा रहा है कि यह जो धन आया है कांग्रेस के पास, इस मामले को कुछ इस तरह से दबा दिया जाए या मुकदमेबाजी में फंसा दिया जाए कि वह बात दरगुजर ही जाए, दिमाग से निकल जाए। शायद यही कांग्रेस की संस्कृति पहले रही है। यह जो अपराध हुआ है भारतीय कानूनों के तहत उससे भारतीय लोकतंत्र को क्षति पहुंची है। क्या हम इसकी उपेक्षा करेंगे?

महोदया, अभी हवाला के मामले में पिछले दिनों तमाम चाहिए सामने आई। हवाला में हुआ यह था कि वह धन भारत के कुछ राजनैतिक दलों ने, राजनीतिज्ञों ने भारत में ले लिया और जो धन भारत में लिया, वह इसलिए लिया कि उनको उसके एवज में कोई पैसा विदेश में दिया गया था। यह जो विदेशी पैसा आ रहा है, इससे भारतीय राजनीति किस तरह प्रभावित हो रही है, यह अपने आप में चिंता की बात है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पर जिस मुस्तैदी से भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए था, मुस्तैदी से ध्यान नहीं दिया गया।

महोदया, जब यह धन आया और जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो इसकी और भी उपेक्षा कर दी गई। आज जब चारों तरफ राजनैतिक भ्रष्टाचार पर हम प्रहार करने की बात कर रहे हैं, आज जब पारदर्शिता की बात की जा रही है, आज जब जवाबदेही की बात की जा रही है, नैतिकता को पुनःवापस लाने की बात की जा रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में हम उस तमाम मामले में गौर नहीं करेंगे कि किस तरह से विदेशी धन यहां आकर भारतीय राजनीति को और भारतीय लोकतंत्र को भ्रष्ट कर कर रहा है? यह एक गंभीर समस्या है। आज कांग्रेस ने चार करोड़ रुपये तो सरेआम लगा दिए और पता नहीं कितना और पैसा मंगाया है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। मैं चाहता हूं, मैडम, कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस प्रकार के प्रश्न की गंभीरता से जांच की जाए कि कौन दल में है, जो पैसा मंगाता है, पैसा लाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं।

महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय दिया। धन्यवाद।

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Madam, the issue is serious. Some political parties have raised funds through their religious outfits. They have not themselves received them directly. You may remember that there was a tremendous uproar and consternation when a hook by Daniel Moynihan was published during Mr. Morarji Dcsai's tenure in our country. This is a very serious issue which is polluting our poliiica! environment, and it should be stopped.

RE. GOVERNMENT'S UTTER NEGLECT OF BASIC PROBLEMS OF WORKING PEOPLE

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, we have a new Prime Minister. I do not know whether this is a new Government, but he is a new Prime Miniter. Since he is a new Ptimc Minister, we ail expect, at least the people expect, that he will not tread on the dotted line of his predecessors Why am I raising this issue? 1 am raising this issue because we have been discussing everything in Parliament, including the Budget, the Government's economic policy, the WTO and everything else, but what is being totally forgotten is the basic problems of the working population of the country, on whom depends implementation of the economic policies. The basic problems of the working population of the country are being constantly ignored, bypassed and neglected. This is the tradition that is being continued. I want to know from Mr. Gujral whether he is going to break new grounds and ensure that something is done to ameliorate the problems.

To give you an example, Madam, the Fifth Central Pay Commission submitted its Report on the 30th of January, 1997. Three months have passed.

The Government has not taken any decision. Only a Committee of Secretaries has been appointed to look into the modalities of formulating the Government's opinion, not implementation. And what is the result? The result is that the Confcdration of the Central Government Trade Unions has called its session to decide for direct agitation. This Commission was set up three years back. The Commission has taken three years to formulate its views and the Government is taking months after months to formualte its stand. I give you another example. The Central Government employees may be considered to be better paid employees, but what about the 90 per cent of the unorganised labour of the country? The Government led by Mr. Rajiv Gandhi had appointed a Commission. There had been a number of Commissions earlier also. Every Commission has recommended that there should be a legislation for the agricultural workers of the count:y. In the last session Mr. Arunachalam came to the House to apologise that he could not keep his promise which he had made in the earlier session that an agricultural workers' Bill would be introduced. There is another tragic situation. I understand that during